



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला मंगलवार 25 अक्टूबर, 2011/3 कार्तिक, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, 18th October, 2011

No. HHC/GAZ/10-40/80-V.—Consequent upon the enactment of the H.P.Judicial Officers (Pay and conditions of service) Act, 2003 and the framing of H.P.Judicial Officers (Pay fixation) Rules, 2010, the following members of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judge(Junior Division) have ben granted the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of Rs. Rs.33090-920-40450-1080-4585 with effect from the dates shown against their names:

Sr. No.	Name of the officer	Date of grant of 1st ACP Scale of Rs.33090-45850
1.	Shri Ramnik Sharma	31.8.2011
2.	Shri Vivek Sharma-II	31.8.2011
3.	Shri Sidharath Sarpal	31.8.2011
4.	Shri Subhash Chand	31.8.2011

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH,
Court of Himachal Pradesh,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, 19th October, 2011*

No. HHC/Admn.3(359)/92.—25 days commuted leave w.e.f 06.9.2011 to 30.9.2011 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Sh. M.R. Rolta, Court Master of this Registry.

Certified that Sh. M.R. Rolta has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. M.R. Rolta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 18th October, 2011*

No. HHC/GAZ/14-320/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 10 days' earned leave w.e.f 12.9.2011 to 21.9.2011 with permission to prefix 10th and 11th September, 2011 being second Saturday and Sunday in favour of Sh. Aslam Beg, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Dehra, H. P.

Certified that Sh. Aslam Beg had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Aslam Beg would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Dehra, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, 21th October, 2011*

No. HHC/Admn.3(149)/80.—10 days earned leave on and with effect from 27.10.2011 to 5.11.2011 with permission to prefix Deepawali holidays falling on 25.10.2011 and 26.10.2011 and suffix Sunday, Gazetted holiday falling on 6.11.2011 and 7.11.2011 is hereby sanctioned in favour of Shri. Faryad Bhatti, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri. Faryad Bhatti is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri. Faryad Bhatti would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th October, 2011

No. HHC/Admn.6(24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (senior Division)-cum-JMIC(I), Paonta Sahib as Additional Chief Judicial Magistrate for Sirmaur Sessions Division, w.e.f 24.10.2011 to 30.10.2011 to look after the urgent work of the court of District and Sessions Judge, Sirmour at Nahan, H. P.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH,
Court of Himachal Pradesh,
Registrar General.

निर्वाचन विभाग

38-एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला-171009, 24 अक्टूबर, 2011

संख्या 3-3/2011-ई.एल.एन.-2114.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2011/पी0पी0एस0-II, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 तदनुसार 25 भाद्र, 1933 (शक) जो कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 के साथ पठित, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में, संशोधन के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
नरेन्द्र चौहान,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001.

दिनांक: 16 सितम्बर 2011.
25 भाद्रा, 1933 (शक्),

अधिसूचना

सं०: 56/2011/पी०पी०एस०-II.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:—

- (i) यह आदेश निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2011 कहा जाएगा ।
- (ii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. पैरा-6क में संशोधन :—

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 (इसके पश्चात, 'मुख्य आदेश' के रूप में संदर्भित) में विद्यमान पैरा-6क, खंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

- '(v) राज्य से लोक सभा या राज्य की विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने उस निर्वाचन में, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के आठ प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों ।'

3. नए पैरा 10ख का अंतर्वेशन:—

मुख्य आदेश के पैरा 10क के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंतर्वेशित किया जाएगा :—

"10ख—रजिस्ट्रीकृत नए दलों (अमान्यताप्राप्त) तथा अमान्यताप्राप्त दलों, जो कि 6 वर्ष से पूर्व मान्यता प्राप्त दल थे, द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायत :—

राज्य की विधान सभा या लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हो :—

(क) विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में —

- (i) राजनीतिक दल राज्य के विधान सभा निर्वाचनों में कम से कम 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) विधान सभा क्षेत्रों पर, और यदि राज्य में विधान सभा में 40 या इससे कम सीट हो, तो कम से कम 5 सीटों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा ;
- (ii) दल द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम संख्याओं तथा नामों के संबंध में सूचना आयोग में निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) के जारी होने की तारीख से तीन पूर्ण दिन पूर्व दे दी जाती हैं ;

- (iii) निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से दल, अधिमान्यता के क्रम में, 10 प्रतीकों का नाम देगा ;
- (iv) दल यह भी शपथपत्र देगा कि यदि दल उपर्युक्त शर्त (i) में निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थी खड़े नहीं करता है तो उनके अभ्यर्थी, उनके प्रतीक आवंटन के दिन, एक ही प्रतीक के आवंटन के हकदार नहीं होंगे; तथा इसके अतिरिक्त, दल आयोग के समक्ष मिथ्या घोषणा करने के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा ।
- (ख) लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन में—
- (i) राजनैतिक दल राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, और यदि राज्य में 5 या इससे कम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हों तो कम से कम दो निर्वाचन क्षेत्रों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा, जिनमें वह अपने अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रतीक आवंटन करवाना चाहता है ;
- (ii) दल द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की कम संख्याओं एवं नामों के सम्बन्ध में सूचना आयोग में निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी होने की तारीख से तीन पूर्ण दिन पहले दे दी जाती है ;
- (iii) निर्वाचनों के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से दल अधिमान्यता क्रम में 10 प्रतीकों का नाम देगा ;
- (iv) दल यह भी शपथ-पत्र देगा कि यदि दल उपरोक्त शर्त (i) में निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों, में न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थी खड़े नहीं करता है, तो उनके अभ्यर्थी, उनके प्रतीक आवंटन के दिन, एक ही प्रतीक आवंटन के हकदार नहीं होंगे तथा इसके अतिरिक्त दल आयोग के समक्ष मिथ्या घोषणा करने के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय दण्डात्मक कार्रवाई का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—

सन्देह दूर करने के लिए एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि:—

- (i) इस अनुच्छेद के अधीन रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक के आवंटन की सुविधा केवल एक बार होगी, या तो लोकसभा या राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन में, जैसा भी दल चयन करता है, और जिस दल ने इस छूट का एक बार लाभ उठा लिया है वह तदनन्तर किसी साधारण-निर्वाचन में इस छूट का पात्र नहीं होगा ;
- (ii) इस पैरा के अंतर्गत दल के अभ्यर्थियों को एक ही चिन्ह के रूप में प्रदान किए गए प्रतीक उन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जिसमें उस दल ने अपने अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं किया है, अन्य दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों अथवा निर्दलीय अभ्यर्थियों को दिए जाने के लिए उपलब्ध होंगे ;
- (iii) यदि दो या दो से अधिक दल एक ही प्रतीक के लिए प्राथमिकता देते हैं, तब ऐसे दलों में से एक के प्रतीक प्रदान किए जाने का प्रश्न लॉटरी द्वारा इस प्रकार निर्णय लिया जाएगा, जैसा आयोग द्वारा यथा निर्देशित हो ;
- (iv) यदि आयोग के लिए किसी कारणवश दल के अभ्यर्थियों को उन प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक प्रदान करना संभव न हो, जिसके लिए उन्होंने इस पैरा के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता दी है, तो मुक्त प्रतीकों की सूची से कोई अन्य प्रतीक, उस पार्टी के परामर्श से, उस दल को दिया जा सकता है ;
- (v) पैरा 10क में किसी बात के निहित होते हुए भी, राजनीतिक दल जो पहले एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल था तथा जिसने 6 वर्ष पूर्व अपनी मान्यता खो दी थी, वह भी, इस पैरा के अंतर्गत दल की मान्यता रद्द होने के 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन में, उस प्रतीक,

जो कि पहले उस दल के लिए आरक्षित था, के आवंटन में एक-बार छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उपखण्ड (iii) में दिए गए शर्त के सिवाय खण्ड (क) या (ख), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करें।

(4) पैरा-12 के उप-पैरा (i) के खण्ड (ग) का प्रतिस्थापन:-

मुख्य आदेश के पैरा-12 के उप-पैरा (i) के विद्यमान खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(ग) पैरा-10 या पैरा-10क या पैरा-10ख में निर्दिष्ट अभ्यर्थी’

आदेश से,

के० एफ० विल्फ्रेड,

भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001.

Dated: 16th September, 2011
25 Bhadra, 1933, (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2011/PPS-II/.—In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India read with Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely:-

- **Short title and commencement:-**
- This Order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2011.
- It shall come into force with immediate effect.
- **Amendment to paragraph-6A:-**

In the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, (hereinafter referred to as the `Principal Order), in paragraph-6A, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :—

- ‘(v) At the last general election to the House of the People from the State, or at the last general election to the Legislative Assembly of the State, the candidates set up by the Party have secured not less than eight percent of the total valid votes polled in the State’.

• **Insertion of new paragraph 10B :-**

After paragraph-10A of the Principal Order, the following paragraph shall be inserted:-

10B—Concession to candidates set up by newly registered (unrecognized) parties and to unrecognized parties which were earlier recognized parties more than 6 years back.

The candidates set up by a registered unrecognized political party at the general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of free symbols, subject to the fulfillment of the following conditions :-

- At a general election to the Legislative Assembly-
- The party sets up candidates at least in 10% (ten percent) of the assembly constituencies in the State, subject to a minimum of five constituencies in States having forty or less seats;
- The intimation with regard to the serial numbers and names of the constituencies concerned are intimated by the party to the Commission latest by three clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is to be issued ;
- The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission for the election;
- The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as may be permissible under the law for making a false declaration before the Commission.
- At a general election to the House of the People –
- The party sets up candidates at least in 10% (ten percent) of the parliamentary constituencies in the State, in which it seeks allotment of a common symbol to its candidates, subject to a minimum of two constituencies in States having less than five parliamentary constituencies allotted to the State;
- The intimation with regard to the serial numbers and names of the constituencies concerned are intimated by the party to the Commission latest by three clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is to be issued;
- (iii) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission for the election;
- (iv) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as may be permissible under the law for making a false declaration before the Commission.

Explanation –

For the removal of doubt, it is hereby clarified that-

- (i) the concession of allotment of common symbol to the candidates of a registered unrecognized party under this paragraph shall be only a one-time facility either at a general election to the House of the People or to a State Legislative Assembly, as the

party may choose, and a party that has availed of this concession once shall not be eligible for the concession in any subsequent general election;

- the symbol allotted as a common symbol to the candidates of a party under this paragraph shall be available for allotment to candidates set up by the other parties or independent candidates in those other constituencies in which that party has not set up its candidates;
- if two or more parties give preference for the same symbol, then the question of allotment of the symbol to one of such parties shall be decided by draw of lots in such manner as may be directed by the Commission;
- if it is not possible for the Commission for any reason to allot a common symbol to the candidates of a party from out of the list of symbols for which it has given its preference under this paragraph, some other symbol from the list of free symbols may be allotted to that party in consultation with that party;
- notwithstanding anything contained in paragraph 10A, a political party which was earlier a recognized political party and which lost its recognition more than 6 years back will also be eligible under this paragraph to the one-time concession of allotment of the symbol which was earlier reserved for the party, at a general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State, held after expiry of six years since the party lost its recognition, subject to the fulfillment of each of the conditions specified under clause(A) or (B), as the case may be, except the condition in subclause (iii) thereof.'

• **Substitution of clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph-12-**

For the existing clause(c) of sub-paragraph (1) of paragraph-12 of the Principal Order, the following clause shall be substituted, namely, :-

“(c) a candidate referred to in paragraph-10 or paragraph-10A or paragraph-10B, ’ .

By order,

K.F.WILFRED,
PRINCIPAL SECRETARY TO THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 अक्टूबर, 2011

सं० ई०एक्स०एन०-ए(३)-४/९३-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-ए(३)-४/९३, तारीख 25.3.1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान अधिकारी (वर्ग-I राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग, आबकारी एवं कराधान अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2011 हैं ।

(2) ये नियम, ई-राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान अधिकारी (वर्ग—। राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध "अ" में,

- क) स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:—
"₹ 10300—34800 + ग्रेड पे ₹ 4400"
- ख) स्तम्भ संख्या: 8 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:—
"आयु : लागू नहीं ।
"शैक्षिक अर्हता : हां । स्तम्भ संख्या 11 के सामने यथाविहित ।"
- ग) स्तम्भ संख्या: 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा,
अर्थात:—
निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा, :—
- (i) आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों, जिनका 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 8 वर्ष का सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा.
..... 55%.
- (ii) अधीक्षक ग्रेड—।। और निजी सहायकों, जो स्नातक हों और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल अपने ग्रेड में की गई लगातार सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा..... 10%.

आबकारी एवं कराधान अधिकारी का पद भरने के लिए निम्नलिखित 69 प्वाइंट आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जायेगा :

- 1 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 2 सीधी भर्ती
- 3 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 4 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 5 सीधी भर्ती
- 6 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 7 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 8 सीधी भर्ती
- 9 प्रोन्नत (लिपिक वर्गीय)
- 10 प्रोन्नत (लिपिक वर्गीय)
- 11 सीधी भर्ती
- 12 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 13 सीधी भर्ती
- 14 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 15 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 16 सीधी भर्ती
- 17 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 18 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 19 सीधी भर्ती
- 20 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 21 प्रोन्नत (निरीक्षक)
- 22 सीधी भर्ती
- 23 प्रोन्नत (लिपिक वर्गीय)
- 24 प्रोन्नत (लिपिक वर्गीय)

25	सीधी भर्ती
26	प्रोन्नत (निरीक्षक)
27	प्रोन्नत (निरीक्षक)
28	सीधी भर्ती
29	प्रोन्नत (निरीक्षक)
30	प्रोन्नत (निरीक्षक)
31	सीधी भर्ती
32	प्रोन्नत (निरीक्षक)
33	सीधी भर्ती
34	प्रोन्नत (निरीक्षक)
35	प्रोन्नत (निरीक्षक)
36	सीधी भर्ती
37	प्रोन्नत (निरीक्षक)
38	प्रोन्नत (लिपिक वर्गीय)
39	सीधी भर्ती
40	प्रोन्नत (निरीक्षक)
41	प्रोन्नत (निरीक्षक)
42	सीधी भर्ती
43	प्रोन्नत (निरीक्षक)
44	प्रोन्नत (निरीक्षक)
45	सीधी भर्ती
46	प्रोन्नत (निरीक्षक)
47	प्रोन्नत (निरीक्षक)
48	सीधी भर्ती
49	प्रोन्नत (निरीक्षक)
50	सीधी भर्ती
51	प्रोन्नत (निरीक्षक)
52	प्रोन्नत (निरीक्षक)
53	सीधी भर्ती
54	प्रोन्नत (लिपिक वर्गीय)
55	प्रोन्नत (निरीक्षक)
56	सीधी भर्ती
57	प्रोन्नत (निरीक्षक)
58	प्रोन्नत (निरीक्षक)
59	सीधी भर्ती
60	प्रोन्नत (निरीक्षक)
61	प्रोन्नत (निरीक्षक)
62	सीधी भर्ती
63	प्रोन्नत (निरीक्षक)
64	प्रोन्नत (निरीक्षक)
65	सीधी भर्ती
66	प्रोन्नत (निरीक्षक)
67	प्रोन्नत (निरीक्षक)
68	सीधी भर्ती
69	प्रोन्नत (लिपिक वर्गीय)

टिप्पण.—रोस्टर प्रत्येक 69 प्वाइंट के पश्चात तब तक दोहराया जायेगा (चक्रानुकमित किया जायेगा) जब तक दी गई प्रतिशतता द्वारा प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जायेगी, जो पद को रिक्त करता है :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र पदधारियों की सेवाकाल के आधार पर उनकी वर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी ।

क (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह आरै कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा। जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.-I उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण.-II उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

- 1 जिला लाहौल एंव स्पिति ।
- 2 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
- 3 रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
- 4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
- 5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
- 6 कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
- 7 जिला किन्नौर ।
- 8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलांड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
- 9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पट्टर तहसील के झारवाड, कुटगढ ग्रामन, देवगढ, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बंगडा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त ।

ख (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती आरै प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेटे नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

(ध) स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

सेवा का प्रत्येक सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1977 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this department Notification No.EXN-A(3)4/93-I dated 24.10.11 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 24th October, 2011

No. EXN-A(3)4/93-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the H.P. Excise & Taxation department Excise & Taxation Officer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997, notified vide Notification No.EXN.A(3)-4/93 dated 25-3-1997 namely:-

1. Short title & Commencement.—(1) These Rules may be called the Himahal Pradesh Excise and Taxation Department Excise & Taxation Officer (Class-I) Gazetted Recruitment & Promotion (Third Amendment) Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in e-Gazette, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A”.—In Annexure ‘A’ to the Himachal Pradesh, Excise & Taxation Department Excise & Taxation Officer Class-I (Gazetted) Rules, 1997 ,

- (e) For the existing provision against column No.4, the following shall be substituted, namely:-
“Rs. 10300-34800+ 4400 Grade Pay”
- (f) For the existing provision against column No.8, the following shall be substituted, namely:-
“Age Not applicable.
Educational qualification: Yes. As prescribed against column No.11.”
- (g) For the existing provision against column No. 11, the following shall be substituted, namely:-

“By Promotion from amongst the following:-

(i) By promotion from amongst the Excise and Taxation Inspectors with 8 years regular service or combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade. 55%
(ii) By promotion from, amongst the Superintendents Grade II and Personal Assistants, who are Graduate and also possess 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the respective grade.10%

For filling up the posts of Excise and Taxation Officer, the following 69 points post based roster shall be followed:

1. Promotee (Inspector)
2. Direct
3. Promotee (Inspector)
4. Promotee (Inspector)
5. Direct
6. Promotee (Inspector)
7. Promotee (Inspector)
8. Direct
9. Promotee (Ministrial)
10. Promotee (Ministrial)
11. Direct
12. Promotee (Inspector)
13. Direct
14. Promotee (Inspector)
15. Promotee (Inspector)
16. Direct
17. Promotee (Inspector)
18. Promotee (Inspector)
19. Direct
20. Promotee (Inspector)
21. Promotee (Inspector)
22. Direct
23. Promotee (Ministrial)
24. Promotee (Ministrial)
25. Direct
26. Promotee (Inspector)

-
27. Promotee (Inspector)
 28. Direct
 29. Promotee (Inspector)
 30. Promotee (Inspector)
 31. Direct
 32. Promotee (Inspector)
 33. Direct
 34. Promotee (Inspector)
 35. Promotee (Inspector)
 36. Direct
 37. Promotee (Inspector)
 38. Promotee(Ministrial)
 39. Direct
 40. Promotee (Inspector)
 41. Promotee (Inspector)
 42. Direct
 43. Promotee (Inspector)
 44. Promotee (Inspector)
 45. Direct
 46. Promotee (Inspector)
 47. Promotee (Inspector)
 48. Direct
 49. Promotee (Inspector)
 50. Direct
 51. Promotee (Inspector)
 52. Promotee (Inspector)
 53. Direct
 54. Promotee(Ministrial)
 55. Promotee (Inspector)
 56. Direct
 57. Promotee (Inspector)
 58. Promotee (Inspector)
 59. Direct
 60. Promotee (Inspector)
 61. Promotee (Inspector)
 62. Direct
 63. Promotee (Inspector)
 64. Promotee (Inspector)
 65. Direct
 66. Promotee (Inspector)
 67. Promotee (Inspector)
 68. Direct
 69. Promotee(Ministrial)

Note.—The roster will be rotated after every 69 point till the representation to all categories is achieved by the given percentange. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

Provided further that for the purpose of promotion a combined seniority of eligible incumbents on the basis of length of service without disturbing their cadre wise seniority shall be prepared.

A(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/ Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officilas who have not served at least one tenure in Tribal/ difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso A(I) supra the “term” in Tribal/ Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such area keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.— For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkall and Gram- panchyat Kashapat, Gram Panchyat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhargal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tesil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Padhar Tehsil Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and south Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

B(1) In all caes of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of the total length of service (including the service rendered on Adhoc basis), in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration of such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior the incumbent ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happen to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Non Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of the Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rule, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc- service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that inter-se- seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged.”

(h) For the existing provisions against column No.17,the following shall be substituted, namely:-

Every Member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

By order,
Sd/-
Principal Secretary(E&T).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

सूर्याश संरक्षिका वालवन्ती पत्नी श्री सोहन देव, गांव दन्दक, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र श्री भीम चन्द, 2. किशन लाल पुत्र श्री प्रेम दास, 3 राम नाथ पुत्र श्री अमर लाल, गांव दन्दक, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

विषय.—मिसल तकसीम नं० 4/न० 10/2011 तकासीम खाता खतौनी नं० 11/11, खसरा नं० 1-5-8, कित्ता 8, महाल लिंगचा बारे।

उक्त प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए परन्तु नोटिस जारी करने के उपरान्त प्रतिवादीगण की असालतन तामील नहीं हो पा रही है। अतः अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की साधारण ढंग से तामील नहीं हो सकती है।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वे तारीख पेशी 14-11-2011 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा की सुनवाई कर दी जाएगी। बाद में कोई भी उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 14-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०	तारीख मरजुआ	तारीख फैसला
13	15-10-2011	5-11-2011

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी छौ, डा० व ग्राम पंचायत चम्हारग, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी छौ, डा० व ग्राम पंचायत चम्हारग, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि उसकी पुत्री का वास्तविक नाम ज्योत्सना शर्मा व जन्म तिथि 21-7-2006 है लेकिन ग्राम पंचायत चम्हारग के अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। जिसे दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बुद्धि सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 9-XIII-A-I/2010

तारीख मजरुआ : 19-8-2011

श्री ईश्वर सिंह

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए दरुस्ती नाम।

हरगाह खास आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री चैतरू, निवासी हलोट, परगणा छोटाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में ईश्वर दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम ईश्वर सिंह दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र पस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 15-11-2011 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17-10-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री दौलत राम पुत्र श्री राम सरण, निवासी गांव दलैया, डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दौलत राम पुत्र श्री राम सरण, निवासी गांव दलैया, डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री अनीता जिसकी जन्म तिथि 4-6-1993 है, को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत टियाली के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

रीतू वर्मा पुत्री श्री बेली राम, निवासी दिखलती, डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रीतू वर्मा पुत्री श्री बेली राम, निवासी दिखलती, डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपना नाम सही करने हेतु (सरीता से रीतू) को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत टियाली के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज चौहान,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सोहन लाल पुत्र श्री रतन दास, निवासी मुन्धाड़ा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री सोहन लाल पुत्र श्री रतन दास, निवासी मुन्धाड़ा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में गुजारिश की है कि मेरे दादा श्री बुद्धु पुत्र स्व0 श्री सोबनु, निवासी मुन्धाड़ा, तहसील रोहडू अरसा लगभग 35 व 40 वर्षों से लापता हैं जिनका उपरोक्त अरसा से आज तक कोई इलम न है। कागजात माल में उपरोक्त दादा का इन्तकाल बदस्तुर चला आ रहा है।

अतः आम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दुरुस्ती बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2011 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजिर आवे तथा अपने उजर पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री काबल सिंह, निवासी अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री काबल सिंह, निवासी अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के

अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके चाचा श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह जिनकी मृत्यु तिथि 28-10-1997 है, का नाम ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में नहीं कटवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब कटवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह का नाम कटवाने एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दीपक ठाकुर पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी झील वांका बाएं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दीपक ठाकुर पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी झील वांका बाएं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी अपनी व भाई विनय कुमार की जन्मतिथियां 18-11-1992 व 17-10-1989 हैं, के नाम ग्राम पंचायत हरिपुर खोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर दीपक कुमार, विनय कुमार के नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री नन्द लाल, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री नन्द लाल, निवासी निहालगढ़, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत

करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री शीतल देवी जिसकी जन्म तिथि 20-12-2006 है, का नाम ग्राम पंचायत निहालगढ़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 18-11-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु० शीतल देवी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी० एस० गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी ग्राम गुरुमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 10-7-2008 को श्रीमती मंजू देवी पुत्री श्री ऋषि पाल, निवासी ग्राम लिसौड़ा, तहसील खतौली, जिला मुज्जफरनगर (यू० पी०) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी ग्राम गुरुमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती मंजू देवी पुत्री श्री ऋषि पाल, निवासी ग्राम लिसौड़ा, तहसील खतौली, जिला मुज्जफरनगर (यू० पी०) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत किशनपुरा में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-11-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 8-11-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Shubh Karan Singh, Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. /2011

Pending for 14-11-2011

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Sh. Parminder Singh s/o Shri Baldev Singh, r/o Village Karsoli, P. O. Kali Bari, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh and Smt. Iqbal Kaur d/o Shri Jarnail Singh and w/o Sh. Parminder Singh s/o Shri Baldev Singh, r/o Village Karsoli, P. O. Kali Bari, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 25-11-2007.

And whereas both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 14-11-2011 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 14-11-2011, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 13-10-2011.

Seal.

SHUBH KARAN SINGH,
Marriage Officer (SDM),
Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th October, 11

No. 6-88/92-Tpt-II.— In partial modification of this Department Notification No. 6-88/92-Tpt-I, dated 17-6-2009 vide which Board of Directors of Himachal Road Transport Corporation was re-constituted, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section-5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 is pleased to appoint Shri J. C Sharma, Secretary to the Hon'ble Chief Minister Himachal Pradesh as Director on the Board of Directors of Himachal Road Transport Corporation in place of Shri Ajay Mittal, Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister Himachal Pradesh with immediate effect in the public interest.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Transport) .